

- लोक वित्त के नियमन के लिए बनायी जानी वाली उस नीति को क्या कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय एवं राजस्व कार्यक्रमों का उपयोग करके राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछनीय प्रभाव डालने का प्रयास करती है तथा करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण उसके महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं?

- राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

- सरकारी आय-व्यय से संबंध किसका होता है? - राजकोषीय व्यवस्था का
- ऐसी राजकोषीय नीति को क्या कहा जाता है, जिसमें जब अर्थव्यवस्था में समग्र व्यय में कमी के कारण मंदी की स्थिति हो, तो कर को कमी और सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए?

- क्षतिपूर्क राजकोषीय नीति (कॉंस द्वारा दिया गया)

- किस सार्वजनिक प्राप्ति से सरकार की परिसम्पत्तियों में कोई कमी नहीं होती और न ही इससे सरकार की देयता बढ़ती है? - राजस्व प्राप्ति (Revenue Receipt)
- सार्वजनिक आय के उस भाग को क्या कहा जाता है, जिससे सरकार की परिसम्पत्तियों का हास होता है या सरकार की देयता में वृद्धि होती है?

- पूंजीगत प्राप्ति (Capital Receipt)

- विनिवेश से प्राप्त आय, बाजार ऋण, राजकोषीय ऋण, बॉन्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आदि किस सार्वजनिक प्राप्ति के उदाहरण हैं?

- पूंजीगत प्राप्ति (Capital Receipt)

- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्ति निरंतर कम हो रही हैं, जबकि राजस्व प्राप्ति लगातार बढ़ रही हैं। यह कथन सत्य है या असत्य? - सत्य
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित प्रावधानों के मुताबिक भारत में सार्वजनिक व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में विभाजित करना बाध्यकारी है?

- अनुच्छेद 112

- जब सार्वजनिक आय की तुलना में व्यय अधिक होता है, तो इसे 'घाटे का बजट या बजटीय अंतर' कहा जाता है। इससे विपरीत स्थिति को क्या कहा जाता है?

- अतिरेक का बजट

- राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के अंतर को राजस्व घाटा (Revenue Deficit) कहा जाता है। राजस्व घाटा को पाटने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है, जिससे व्याज के रूप में राजस्व व्यय बढ़ता जाता है। यदि यही क्रम चलता रहता है, तो अर्थव्यवस्था किस संकट में में फंस जाती है? - ऋण जाल (Debt Trap)

- राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकारों के व्ययों तथा प्राप्ति का अंतर बजटीय घाटा (Budget Deficit) कहलाता है, जिसको सरकार नई ऋणियां जारी करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष आहरणों से पूरा करती है। भारत में किस वर्ष से बजटीय घाटा आकलित नहीं किया जाता है?

- वर्ष 1998-99 से

- वर्ष 1997-98 में भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए समझौते के अनुसार रिजर्व बैंक तदर्थ ट्रेजरी बिल नहीं जारी करेगा, जबकि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करेगी। इस ऋण को क्या कहा जाता है? - अग्रिम (Advance)

- बजटीय घाटा में सार्वजनिक ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के योगदान को जोड़ने पर मौद्रिक घाटा (Monetised Deficit) प्राप्त होता है। इस घाटा से चलन में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या नई मुद्रा का पता चलता है। भारत में केंद्र सरकार ने किस वर्ष से मौद्रिक घाटा आकलित करना बंद कर दिया है?

- वर्ष 1998-99

सार्वजनिक व्यय

सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure) में रक्षा, प्रशासन, सामाजिक, सामुदायिक तथा आर्थिक संवर्धन, राज्यों को सहायता अनुदान, रेल, डाक एवं तार तथा नागरिक कार्यों पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है।

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण (Public Debt) सरकार द्वारा लिया गया वह ऋण है जो किसी आकस्मिक एवं अस्थायी आवश्यकताओं, उत्पादन कार्यक्रमों एवं सामाजिक विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए लिया जाता है।

सहायक अनुदान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में निहित प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान (Grants in Aid) अपने राजस्व अंतरालों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। राज्यों को ऐसी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है जो उसके अनुमोदन से शुरू की गई हो।

सार्वजनिक खाता

सार्वजनिक खाते या आय-व्यय के लेखे (Public Account) में सरकार द्वारा प्राप्त धन यथा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा जमा किया



- बजटीय घाटा, सार्वजनिक ऋण (सकल उधार) तथा अन्य देयताओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है?
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)
- राजकोषीय घाटा तथा ब्याज अदायगी के अंतर को क्या कहा जाता है?
- प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)
- बजट घाटा (सबसे छोटा घाटा), राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा और राजकोषीय घाटा में से सबसे बड़ा घाटा कौन-सा है?
- राजकोषीय घाटा
- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA) राजकोषीय घाटे के अलावा और किससे संबंधित है?
- राजस्व घाटा (Revenue Deficit)
- किस अधिनियम के अनुसार, राजस्व घाटा तथा वित्तीय घाटा में कमी के लिए ही लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं, प्राथमिक घाटा के लिए नहीं?
- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA), 2003
- मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में संशोधन के लिए किया गया?
- एन.के. सिंह
- आठवीं पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या था?
- लोक उद्यमों का अंशदान
- भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच करों का विभाजन किया गया है?
- 7वीं अनुसूची में
- सामान्यतः जिन करों का अंतराज्यीय आधार है, उनको केंद्र द्वारा तथा जिनका स्थानीय आधार है, उनको राज्यों द्वारा लगाया जाता है। संप सूची में करों की 12 मदें हैं, जबकि राज्य सूची में करों की कितनी मदें का उल्लेख है?
- 19 मदें
- उस कर को क्या कहा जाता है, जिसका विवर्तन (Shifting) नहीं होता तथा जिसका कराघात (Incidence of taxes) और कराघात (Impact of taxes) दोनों एक ही व्यक्ति या संस्था पर होता है?
- प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

गया भविष्य निधि, अल्प बचत संग्रहण एवं अन्य जमाएं जिसके लिए सरकार बैंक का कार्य करती है, को समाहित किया जाता है। सामान्यतः यह धन सरकार को नहीं होता है क्योंकि यह धन सरकार को पुनः जमाकर्ता को वापस करना पड़ता है। सार्वजनिक खाते से धन अदायगी हेतु सरकार को संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

आकस्मिक कोष

आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त धन आकस्मिक कोष (Contingency Fund) कहलाता है। परंतु आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् संसद की अनुमति से उतना ही धन संचित कोष से निकालकर पुनः आकस्मिक कोष में जमा करना पड़ता है।

आउटकम बजट

बजट का वह स्वरूप जिसमें किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित की जाने वाली धनराशि के साथ-साथ अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किए जाने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना संभव हो सके।

घाटे का बजट

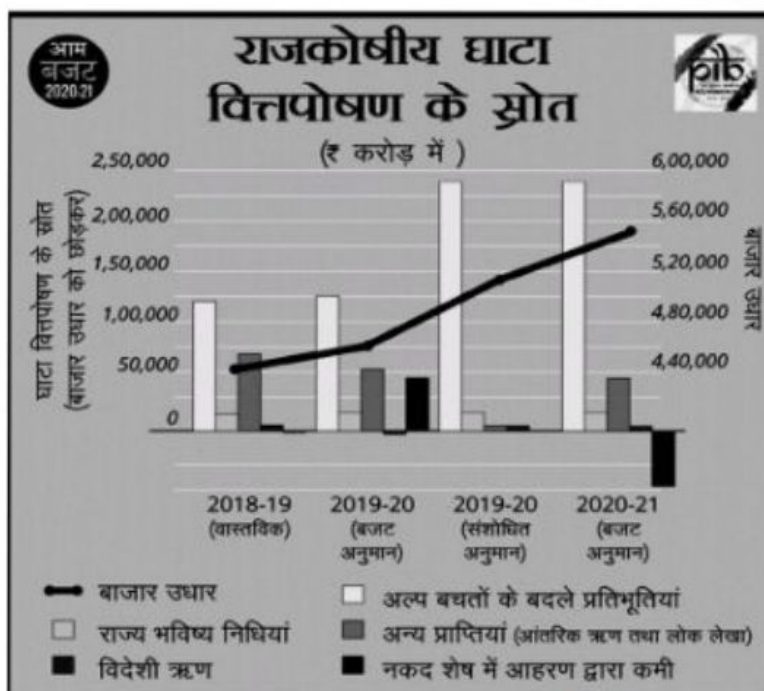
ऐसा बजट जिसमें सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से करों से प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया जाता है।

आधिक्य का बजट

कुल मांग में कमी करने और आर्थिक क्रियाओं के स्तर को घटाने के उद्देश्य से (विरोध रूप में मुद्रा स्फीति के समय में) सरकार की आय को उसके व्यय की तुलना में अधिक रखा जाता है।

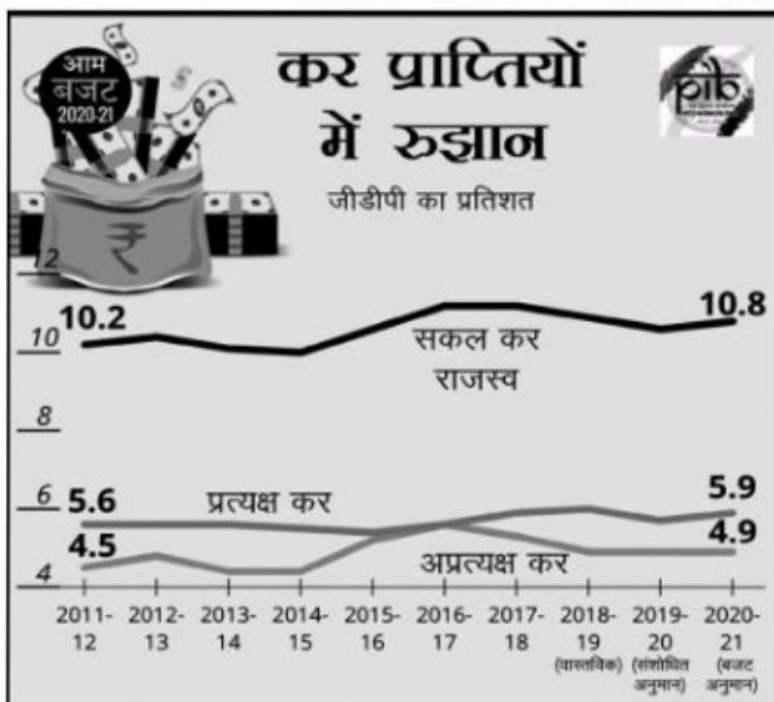
निष्पादन (Performance) बजट

ऐसी बजट प्रक्रिया जिसका आधार सरकार के कार्यक्रम, क्रियाएं एवं योजनाएं होती हैं तथा जिसमें सरकारी व्यय का विश्लेषण मौद्रिक तथा परिमाणिक दोनों प्रकार से किया जाता है।



राजकोषीय नीति एवं सार्वजनिक वित्त

- भारत में राजकोषीय घाटे की संकल्पना का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया?
- डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा (1991 में)
- अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) के तहत करापात तथा कराघात दोनों अलग-अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पर पड़ता है। इसमें करों के मौद्रिक भार का क्या होता है?
- कर विवर्तन (Shifting of Taxes)
- किस समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया?
- सी. रंगराजन समिति
- चालू खाता (Current Account) से हमारा आशय अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रदर्शन से होता है। परंतु जुड़वां घाटा (Twin Deficit) किसे कहा जाता है?
- चालू खाता घाटा एवं राजकोषीय घाटा को
- जब वस्तुओं पर कर उसके मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है?
- मूल्यानुसार कर (Ad-valorem Tax)
- जब वस्तुओं पर कर उसके मूल्य के अनुसार आरोपित न करके मात्रा के अनुसार आरोपित किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है?
- मात्रात्मक कर या विशिष्ट कर
- भारत में कौन-सा शुल्क मूल्यानुसार तथा विशिष्ट कर दोनों रूपों में लगाया जाता है?
- सीमा शुल्क
- जब कर एक निश्चित दर से लगाया जाता है, चाहे कर का आधार कुछ भी क्यों न हो, तो वह आनुपातिक कर (Proportional Tax) कहलाता है। भारत कौन-सा कर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है?
- सेवा कर (Service Tax)
- जब कर की दर कर-आधार में वृद्धि होने के बाद कम होती जाती है, तो उसे अवरोही कर (Degressive Tax); जब कर के आधार में वृद्धि होने के साथ-साथ कर की दर में वृद्धि होती जाती है, तो उसे अग्रोही कर (Regressive Tax); तथा जब कर की दर शुरू में कर के आधार में वृद्धि होने पर बढ़ती है, परंतु बाद में स्थिर हो जाती है तो उसे प्रगतिशील कर (Progressive Tax) कहा जाता है। भारत में आयकर किस प्रकार का कर है?
- प्रगतिशील कर (Progressive Tax)



जेंडर बजट

बजट का वह स्वरूप जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत महिला अधिकारिता के प्रयासों के लिए समुचित धनवर्तन के साथ-साथ सरकारी आय-व्यय का प्राथमिकताओं को इस प्रकार निर्धारित करना जिससे लैंगिक संस्कार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हों।

विनियोग विधेयक

अनुदान मांगों के लिए धन की व्यवस्था संचित कोष से की जाती है। परंतु संचित कोष से तब तक कोई धन नहीं निकाला जा सकता है, जब तक कि लोकसभा उसे पारित न कर दे। अतः अनुदान मांगों एवं धारित व्ययों को पूरा करने के लिए जो विधेयक लोकसभा में संचित कोष से धन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वह विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) कहलाता है।

विनियोग बजट

विनियोग या व्यय बजट (Expenditure Budget) से तात्पर्य उस बजट से होता है, जिसका प्रयोग सरकार द्वारा सरकारी विभागों एवं सेवाओं के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसमें गैर-योजना व्यय शामिल होता है।

वित्त विधेयक

वित्त विधेयक (Finance Bill) में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए कर संबंधी प्रस्ताव सम्मिलित होता है। वित्त विधेयक में सरकार के लेवी समापन, करों की माफ़ी या करों का नियमन सम्मिलित होता है। वित्त विधेयक को लागू करने के पूर्व संसद इस पर विचार करती है एवं आवश्यक संशोधन करके पारित करती है। स्मरण-पत्र, जिसमें वित्त विधेयक में निहित प्रावधानों का विस्तार से वर्णन होता है, बजट दस्तावेजों के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य वित्त विधेयक में सम्मिलित प्रस्तावों को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करना होता है।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व						
वर्ष/कर	CT	TOI	CU	UED	ST	GST
2013-14	3.51	2.16	1.53	1.52	1.38	-
2014-15	3.44	2.13	1.51	1.51	1.35	-
2015-16	3.29	2.09	1.53	2.09	1.54	-
2016-17	3.16	2.37	1.47	2.49	1.66	-
2017-18	3.34	2.52	0.75	1.51	0.48	2.59
2018-19PA	3.49	2.49	0.62	1.22	-	3.06
2019-20BE	3.60	2.71	0.70	1.40	-	3.10

BE: बजट अनुमान, PA: अंतिम वास्तविक आंकड़े, CT: कॉर्पोरेट कर, TOI: कॉर्पोरेट के अलावा आयकर, CU: कस्टम, UED: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ST: सेवा कर, GST: वस्तु एवं सेवा कर

- निष्पेक्षा द्वारा अपने कर्मचारियों को नकद भुगतान के अतिरिक्त जो सुविधा प्रदान की जाती है, उसके समग्र मूल्य पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है?
- **फ्रिंज बेंनिफिट टैक्स (FBT)**
- यदि करारोपण की दर में वृद्धि कर दी जाये, तो सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व बढ़ जायेगा, परंतु राजस्व में यह वृद्धि एक सीमा तक ही होगी। क्यों की दरों में इस सीमा से अधिक वृद्धि कर दिए जाने पर कर राजस्व में कमी आयेगी। कर की दर और उससे प्राप्त कर राजस्व के मध्य इस संबंध का रेखीय चित्रण क्या कहलाता है?
- **लाफर वक्र (Laffer Curve)**
- किसी कम्पनी द्वारा अर्जित किए गए सकल लाभ पर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर निगम कर अथवा कम्पनी लाभ कर (Corporate Tax) कहलाता है। भारत में निगम कर की किस प्रकार की प्रणाली लागू है?
- **विभेदात्मक प्रणाली**
- विभेदात्मक निगम कर प्रणाली के तहत घरेलू तथा विदेशी कम्पनियों के लिए निगम कर की दरें अलग-अलग होती हैं। भारत में घरेलू कम्पनियों के लिए निगम कर वर्ष 2015-16 के बजट में 24.99 प्रतिशत निगम कर का प्रस्ताव किया गया था। विदेशी कम्पनियों के लिए यह कर कितना प्रतिशत है?
- **लगभग 40 प्रतिशत**
- कर की चोरी रोकने तथा प्रदर्शन प्रभाव के वशीभूत होने वाले उपभोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत में सर्वप्रथम 1 अप्रैल, 1958 से व्यय कर (Expenditure Tax) लगाया गया। इसे अब तक तीन बार शुरू और दो बार (1962 और 1964) में बंद कर दिया गया। अंतिम बार इसे फिर कब शुरू किया गया था? - **नवंबर 1987**
- केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लगाये जाने वाले कर को क्या कहा जाता है?
- **सम्पदा शुल्क (Estate Duty)**
- भारत में सम्पदा शुल्क पहली बार 1953 में लगाया गया। 1984 में कृषि भूमि एवं सम्पत्तियों लगने वाले सम्पदा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। गैर कृषि भूमि तथा सम्पत्तियों पर लगने सम्पदा शुल्क को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? - **वर्ष 1985**
- भारत में संयुक्त हिंदू परिवारों, व्यक्तियों तथा कम्पनियों के निवल धन और पूंजी पर एक वार्षिक कर के रूप में धन कर (Wealth Tax) किस समिति अनुशंसा पर पहली बार 1957 में लगाया गया?
- **केल्डर समिति**
- भारत में उपहार कर 1958 में केल्डर समिति की अनुशंसा पर लगाया गया। यह कर उपहार देने वाले पर लगाया जाता है या लेने वाले पर?
- **देने वाले पर**

शून्य बजट प्रणाली

शून्य बजट प्रणाली (Zero Base Budgeting) में गत वित्तीय वर्ष के व्यय का कोई उल्लेख नहीं होता है। शून्य बजट प्रणाली के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि जो व्यय गैर-योजना व्यय के रूप में विकास कार्यों में किए जाते हैं, उनका पूंजी निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है। शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग सं.र. अमेरिका में किया गया था। भारत में शून्य बजट प्रणाली मात्र एक बार 1985 में प्रचलन में लायी गई थी।

घाटे की वित्त व्यवस्था

जब कुल राजकीय व्यय समस्त स्रोतों से प्राप्त आय से अधिक हो जाता है तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन (Deficit Financing) कहा जाता है। जब किसी देश की आर्थिक प्रगति आवश्यक धन के अभाव के अवरुद्ध हो जाती है, तब आर्थिक क्रियाओं को लागू करने के उद्देश्य से धन की व्यवस्था की जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार घाटे का बजट बनाती है, जिसमें आय की तुलना में व्यय करने का प्रावधान अधिक होता है। अधिक व्यय को पूरा करने एवं आर्थिक व्यवस्था को गतिशील बनाने हेतु बचत को प्रोत्साहित करना, कर लगाना, विदेशों से तथा देश से ऋण लेना तथा नई करेंसी का मुद्रण करना आदि उपाय किए जाते हैं।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) प्राप्तियों में व्याज और प्रशासनिक प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। केंद्रीय गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में विभागीय उपक्रमों से होने वाला लाभ सम्मिलित होता है। ध्यातव्य है कि केंद्र से संबंधित विभागीय उपक्रमों में रेलवे, प्रेस एवं जनसंचार, मुद्रा, टकसाल आदि तथा साथ में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं वित्तीय संस्थाएं भी सम्मिलित होती हैं। राज्य के गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में विभागीय उपक्रमों तथा विद्युत परिषदों एवं सिंचाई जो व्यापार के रूप में सम्मिलित की जाती है और वनों से प्राप्त लाभ सम्मिलित होता है।

राजकोषीय नीति एवं सार्वजनिक वित्त

- देश में निर्माण की विभिन्न चरणों में उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क लगाने की दो प्रणालियाँ रही हैं- मैन्यूफैक्चर्स वेल्थ एडेड टैक्स (मैनवैट) तथा मॉडिफाइड वेल्थ एडेड टैक्स (मॉडवैट)। इन दोनों में से किसके तहत अंतिम रूप से तैयार वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है? - **मॉडवैट**
- कौन-सा कर विश्व का प्राचीनतम शुल्क है, जिसको व्यापारियों के लाभ पर लगाया जाता था? - **सीमा शुल्क (Excise Duty)**
- वर्तमान समय में सीमा शुल्क वस्तुओं के निर्यात और आयात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क या तो मूल्यानुसार लगाया जाता है (जिसे Ad Valorem Tax कहते हैं) या मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार वस्तुओं के निर्यात और आयात पर लगाये जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? - **विशिष्ट कर (Specific Tax)**
- विभिन्न करों से प्राप्त राशि को भारत की सौचित निधि में जमा किया जाता है। इस निधि में जमा धन का किसकी अनुमति के बिना व्यय नहीं किया जा सकता? - **संसद**
- भारतीय संविधान में सेवा कर का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु संविधान की 7वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार प्रथम और द्वितीय सूची में वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य मद पर चाहे तो कर लगा सकती है। भारत सरकार ने किस वर्ष पहली बार 3 सेवाओं टेलीफोन, बीमा, और स्टॉक दलाली पर सेवा कर लगाया? - **वर्ष 1994-95 में (वित्त मंत्री- डॉ. मनमोहन सिंह)**
(अब सेवा कर को जीएसटी में शामिल कर दिया गया है।)
- मैनवैट के तहत उत्पाद शुल्क उत्पादन के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। भारत में इस कर का प्रचलन 31 मार्च, 1986 तक रहा। अंतिम रूप से तैयार वस्तु के कुल मूल्य पर न लगाकर केवल बढ़े हुए मूल्य पर लगाये जाने वाले मॉडवैट को भारत में किस समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल, 1986 को लागू किया गया? - **एल.के. झा समिति**
- सेनवैट (CENVAT: Central Value Added Tax) के तहत मॉडवैट की विभिन्न दरों को एकीकृत दर में बदला गया है। भारत में सेनवैट पहली बार कब लागू किया गया? - **1 अप्रैल, 2000 को**
- कौन-सा घरेलू उपभोग कर आरोपित एक यथा मूल्य कर है, जिसे उत्पादन बिंदु से उपभोग बिंदु तक प्रत्येक स्तर पर एकत्र किया जाता है? - **मूल्य वर्द्धित कर (VAT: Value Added Tax)**
(यह विक्री कर का प्रतिस्थापनीय कर है, जिसके तहत उत्पाद के प्रत्येक चरण में केवल बढ़े हुए मूल्य पर कर लगाया जाता है। यह उपभोग कर का एक प्रकार है जिसे सामान्य विक्री कर भी कहा जाता है।)
- वैट का प्रतिपादन वर्ष 1918 में जर्मन उद्योगपति डॉ. डब्ल्यू. वान सिमेन्स ने किया था। सबसे पहले इसको वर्ष 1954 में किस देश में लागू किया गया? - **फ्रांस में**
- भारत में वैट लगाने की संसुति राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1956-57 में ही कर दी थी। वैसे वैट लगाने के लिए सुझाव देने के लिए 16 नवंबर, 1999 को किस समिति का गठन किया गया? - **असीम दास गुप्ता समिति**
- असीम दास गुप्ता समिति ने अपनी संसुति 17 जनवरी, 2005 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम को दी। इस पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद किस तिथि से भारत में वैट लागू हुआ? - **1 अप्रैल, 2005**
- वर्तमान में सभी राज्यों ने वैट लागू कर दिया है। हरियाणा वैट लागू करने वाला पहला राज्य है। किस राज्य में वैट सबसे अंत में 1 जनवरी, 2008 को लागू किया गया? - **उत्तर प्रदेश**

गैर-योजना अनुदान

गैर-योजना अनुदान (Non-Plan Grants) में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग के अनुमोदन पर दिया जाने वाला अनुदान जो विशिष्ट योजनाओं से सम्बद्ध होती है, को सम्मिलित किया जाता है।

गैर-योजना ऋण

केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अल्प बचत संग्रह के बदले दिया जाने वाला ऋण गैर-योजना ऋण (Non-Plan Loan) होता है। गैर-योजना ऋण संप्रदाय शासित क्षेत्रों को अपने गैर-योजना अंतर को पूरा करने के लिए एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी पूंजी हानियों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

गैर-योजना व्यय

गैर-योजना व्यय (Non-Plan Expenditure) में प्रतिरक्षा, व्याज, भुगतान, अनुदान और राजकीय सहायता सम्मिलित की जाती है। इसके अतिरिक्त गैर-योजना व्यय में पूर्ववर्ती योजनाओं द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के रक्षण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य अनुसंधान योजनाओं को जारी रखने तथा ऊर्जा संस्थानों को चालू रखने के लिए किए गए व्यय भी सम्मिलित होते हैं।

ऋण परिवर्तन

किसी सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता पर यदि सरकार उसका वास्तविक भुगतान न करके उस स्थान पर दूसरे नए ऋणपत्र को जारी करती है तो यह प्रक्रिया ऋण परिवर्तन (Debt Conversion) कहलाती है।

वित्तीय घाटा

वित्तीय घाटे (Fiscal Deficit) का आशय उस स्थिति से है, जब सरकार का कुल विनियोग कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। सकल या कुल विनियोग से आशय राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में पुनर्देयताओं से



- वेट के कारण राज्यों को यदि कम राजस्व प्राप्त होता है, तो इसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? - **केंद्र सरकार**
- नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टोबिन ने 1978 में विदेशी मुद्रा बाजार में समग्र लेन-देन पर कर लगाने का सुझाव दिया था। इस कर क्या कहा जाता है? - **टोबिन कर**
- जब केंद्र सरकार का व्यय आय से अधिक होता है, तो उस समय कैसा वित्त प्रबंधन किया जाता है? - **घाटे की वित्त व्यवस्था**
- मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग करता है? - **राज्य**
- किन करों को केंद्र आरोपित करता है, इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है? - **केंद्रीय उत्पाद शुल्क व आयकर**
- स्टाम्प शुल्क, दवाओं तथा सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? - **राज्य को**
- औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के परिणामस्वरूप कौन-सा कर संघ राजस्व का पहला मुख्य स्रोत है? - **संघीय उत्पाद शुल्क**
- आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, सम्पत्ति कर, व्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? - **केंद्र सरकार**
- कौन-से कर केंद्र व राज्य दोनों द्वारा आरोपित किए जाते हैं एवं इनका स्थानांतरण दूसरों पर किया जा सकता है? - **अप्रत्यक्ष कर**
- किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? - **अप्रत्यक्ष कर**
- किसी देश में करों के भार का आकलन करने के लिए किस अनुपात का प्रयोग किया जाता है? - **कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात**

एवं इसके विपरीत कुल प्राप्तियों से तात्पर्य पूंजी एवं राजस्व से है। ध्यातव्य है कि उधार ली गई राशि इसमें सम्मिलित नहीं होती है परंतु व्यवहार में कुल प्राप्तियों में यह भी सम्मिलित रहता है। वित्तीय घाटा वास्तविक घाटा होता है। ध्यातव्य है कि वित्तीय घाटे को राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है।

प्राथमिक घाटा

जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है तो शेष राशि का प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) कहा जाता है।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज (अदा किया गया)

बजटीय घाटा

बजटीय घाटा (Budget Deficit) राजस्व तथा पूंजीगत खातों के अंतर्गत दिखायी जाने वाली समस्त प्राप्तियों तथा समस्त व्यय का अंतर होता है।

बजटीय घाटा = राजस्व प्राप्ति + पूंजीगत प्राप्तियां - आयोजन व्यय - गैर आयोजन व्यय

राजस्व घाटा

जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम होती हैं तो इस रूप में होने वाला अतिरिक्त व्यय राजस्व घाटा (Revenue Deficit) कहलाता है।

सहायक अनुदान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में निहित प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान (Grants in Aid) अपने राजस्व अंतरालों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। राज्यों को ऐसी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है जो उसके अनुमोदन से शुरू की गई हो।

राजकोषीय नीति एवं सार्वजनिक वित्त

- विकसित देशों में करों का बड़ा अंश प्रत्यक्ष करों के माध्यम से जुटाया जाता है। भारत में यह किन करों के माध्यम से जुटाया जाता है? - **प्रत्यक्ष कर**
- रजिस्टर्ड कम्पनियों और निगमों पर आरोपित कर क्या कहलाता है? - **निगम कर**
- किस सम्पत्ति का आकलन उसके बाजार मूल्य में से दायित्वों को घटाने पर प्राप्त होता है और कृषि भूमि, भविष्य निधि और जीवन बीमा राशि को इस कर के आकलन में नहीं लिया जाता है? - **निवल सम्पत्ति**
- भारत में सबसे पहले आयकर जेम्स विल्सन द्वारा कब लाया गया था? - **24 जुलाई, 1860 को**
- आयात-निर्यात मर्चों पर आरोपित कर सीमा शुल्क कहलाता है। सीमा शुल्क ढांचे में परिवर्तन किस समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है? - **राजा जी. खेलेया समिति**
- केंद्रीय बजट 1998-99 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए कौन-सी तीन योजनाएं चलायी गई? - **सरल योजना, समाधान योजना और सम्मान योजना**
- ईमानदार आय करदाताओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 1998-99 में किस योजना का प्रस्ताव किया गया? - **सम्मान योजना**
- वर्ष 2002-03 में किस योजना के तहत आय करदाताओं को इंटरनेट के माध्यम से सभी जानकारी प्रदान करने तथा कर जमा करने की सुविधा दी गई? - **सम्पर्क योजना**
- पैन 10 अंकीय एक विशेष संख्या है, जिसको आयकर विभाग या उसके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसको वर्ष 1998-99 के केंद्रीय बजट के तहत प्रारम्भ किया गया। पैन का पूरा रूप क्या है? - **परमानेंट अकाउंट नंबर**
- कृषि जनित आय को पैन से मुक्त रखा गया है या नहीं? - **मुक्त रखा गया है**
- जनवरी 2007 में म्यूचुअल फंड में अवैध आय को निवेशित होने से रोकने तथा म्यूचुअल फंड से होने वाली आय को कर दायरे में लाने के उद्देश्य से कौन-सा नंबर प्रारम्भ किया गया? - **मिन (म्यूचुअल फंड आइडेंटिफिकेशन नंबर)**
- पैन की तर्ज पर अप्रत्यक्ष करदाताओं के लिए जनवरी 2004 में टिन का प्रस्ताव किया गया। टिन का पूरा रूप क्या है? - **टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर**
- भारतीय संविधान के 12वें भाग में किन अनुच्छेदों में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है? - **अनुच्छेद 264 से 300 तक**
- भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में तीन प्रकार के सहायता अनुदानों तथा उन परिस्थितियों का उपबंध है, जिनमें केंद्र यह अनुदान राज्यों को प्रदान कर सकता है? - **अनुच्छेद 273, 275 तथा 282**
- अनुच्छेद 292 के तहत भारत सरकार संचित निधि की जमानत पर उधार ले सकती है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों पर उधार लेने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है अर्थात् कोई भी राज्य भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता है? - **अनुच्छेद 293**
- आय कर भारत सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। कृषि आय कर किस सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? - **राज्य सरकार**
- ऐसी मद, जिनका उल्लेख केंद्र तथा राज्य दोनों सूचियों में नहीं किया गया है, यथा- उपहार कर, व्यय कर, पर करारोपण का अधिकार किसका है? - **केंद्र सरकार**

लेखानुदान

लेखानुदान (वॉट आन अकाउंट) का शब्दिक अर्थ सरकार के खातों पर मत होता है। जब तक नई सरकार बन नहीं जाती तब तक कामचलाऊ सरकार को रोजमर्रा के खर्च जैसे स्टाफ के वेतन आदि के लिए धन की जरूरत होती है। संविधान के अनुसार, संसद की मंजूरी के बिना सरकार कोई धन खर्च नहीं कर सकती। ऐसे में कुछ महिने का खर्च चलाने के लिए सरकार लेखानुदान के जरिए संसद की मंजूरी लेती है। हालांकि लेखानुदान के लिए आंतरिम बजट शब्द अक्सर प्रयोग किया जाता है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। लेखानुदान बजट के खर्चों तक ही सीमित है जबकि आंतरिम बजट के खर्चों के साथ प्राप्तियां भी शामिल होती हैं। लेखानुदान आमतौर पर दो या तीन माह के लिए यानी जब तक नियमित बजट नहीं आता, तब तक की अवधि के लिए होता है। किसी भी दशा में यह छह माह से ज्यादा की अवधि के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद की दो बैठकों के बीच छह माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।

सब्सिडी/राजसहायता

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पारिवारिक क्षेत्रों या व्यापार को सस्ती कीमतों पर उपभोग या उत्पादन हेतु प्रदत्त सहायता राजसहायता (Subsidy) कहलाती है। वस्तुतः सब्सिडी किसी वस्तु की लागत और उसके बाजार मूल्य का अंतर होती है।

प्रत्यक्ष कर

वह कर जिसे आगे किसी दूसरे पर खिसकाया (Shift) नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) कहलाता है। प्रत्यक्ष कर का भार उसी व्यक्ति को सहना होता है, जिस पर वह प्रारम्भ में लगाया जाता है। उदाहरणतः, निजी आयकर, कर्मचारियों द्वारा दिया गया सामाजिक सुरक्षा कर, मृत्यु कर इत्यादि।



- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार सौचित निधियों, आकरस्मिक निधियों तथा लोक खाते में जमा धनराशियों आदि का विनियमन संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानमंडल द्वारा किया जायेगा? - अनुच्छेद 283
- लोकसेवकों तथा न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों तथा अन्य राशियों को यथास्थिति केंद्र अथवा राज्यों के लोक खाते में जमा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? - अनुच्छेद 284
- क्या कोई राज्य अपने राज्य के बाहर विद्युत या जल खपत या बिक्री पर अथवा माल के क्रय-विक्रय पर अथवा निर्यात एवं आयात पर कर लगा सकता है? - नहीं
- करों के आय का केंद्र एवं राज्यों में वितरण तथा राज्यों को इस आय का अंश निर्धारित करने तथा राज्यों के राजस्व में सहायक अनुदानों को विनियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 में किस आयोग के गठन का प्रावधान है? - वित्त आयोग
- भारत के वित्त आयोग की स्थापना किस देश के अनुदान आयोग से प्रेरित होकर की गई है? - ऑस्ट्रेलिया
- वित्त आयोग करों के विभाजन, अनुदान तथा अन्य मामलों पर जो इसे सौंपे गए हों, पर अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? - राष्ट्रपति को
- राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या इससे पहले यदि वह उचित समझे, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पहला वित्त आयोग, जिसकी नियुक्ति नवंबर 1951 में की गई थी, के अध्यक्ष के.सी. नयोगी थे। नवंबर 2017 में गठित 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? - एन.के. सिंह
- 15वें वित्त आयोग ने कर राजस्व में राज्यों की कुल हिस्सेदारी को 14वें वित्त आयोग की तुलना में एक प्रतिशत कम कर कितना निर्धारित किया है? - मात्र 41%
- किस वित्त आयोग को संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के संदर्भ में पहली बार राज्यों की समेकित निधि में संसाधन वृद्धि हेतु उपाय सुझाने को कहा गया था, जिससे राज्यों द्वारा पंचायत एवं नगरपालिकाओं आदि को संसाधनों की पूर्ति की जा सके? - 11वां वित्त आयोग

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) से आशय कीमतों पर सरकार द्वारा लगाये जाने वाले अधिभार से है। प्रत्येक व्यक्ति, संस्था एवं समूह से कीमत आधार में वृद्धि करके सरकार आवश्यक धन प्राप्त करती है। इस कर का बोझ अंतिम रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर में करधान और करपात दोनों अलग-अलग व्यक्तियों पर होता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है।

आयकर

एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति की आय प्राप्तियों पर लगने वाला कर आयकर (Income Tax) कहलाता है। ध्यातव्य है कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

प्रगामी कर

करों की वह क्रमवद्ध व्यवस्था जिसमें अधिक आय श्रेणी वाले लोगों के लिए करों की दर अधिक होती है, प्रगामी कर (Progressive Tax) कहलाती है। इसमें आय बढ़ने के साथ-साथ करों की दर भी बढ़ती जाती है।

उत्पाद शुल्क

देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं पर लगने वाला कर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) कहलाता है। उत्पादन शुल्क एक वस्तुकर है जो वस्तु की वास्तविक बिक्री पर नहीं बल्कि वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है।

विनियोग कर

होटल व्यव, जहाँ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के ठहरने का किराया 500 रुपये या इससे अधिक है, पर विनियोग कर (Expenditure Tax) लगाया जाता है। वर्तमान में विनियोग कर 25% है। विनियोग कर में होटल में ठहरने का किराया, भोजन का व्यय, शराब एवं अन्य मदों पर व्यय सम्मिलित है। यह कर विदेशी लेन-देन या राजनयिकों पर नहीं लगाया जाता है।

राजकोषीय नीति एवं सार्वजनिक वित्त

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल बचत					
	2011-12	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल बचत	34.6	32.2	31.1	30.3	30.5
सार्वजनिक	1.5	1.0	1.2	1.7	1.7
निजी कॉरपोरेट	9.5	11.7	11.9	11.5	11.6
परिवार सेक्टर	23.6	19.6	18.0	17.1	17.2
निवल वित्तीय बचत	7.4	7.1	8.1	6.3	6.6
वास्तविक बचत	16.3	12.5	9.9	10.8	10.6
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय । आर्थिक समीक्षा 2019-20					

- आय तथा व्यय का व्यवस्थित विवरण 'बजट' कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का उल्लेख है, जिसे बजट मान लिया गया है?
- अनुच्छेद 112
- किस प्रकार के बजट में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, मशीनों, उपकरणों, यात्रा व्यय आदि के रूप में किए जाने वाले विविध व्ययों तथा विभिन्न मदों से होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु इस बात का ज़ोर नहीं दिया जाता कि इससे क्या-क्या परिणाम प्राप्त करना है?
- पारम्परिक बजट (Traditional Budget)
- आउटकम बजट सामान्य बजट की गुणवत्ता परीक्षण का एक माध्यम है। इस प्रकार के बजट में वित्तीय प्रावधानों को परिणामों के संदर्भ में देखा जाता है, जिसके तहत एक निश्चित समयावधि में संभावित परिणामों को बदलने के लिए विशेष रणनीति अपनायी जाती है। भारत में पहली बार आउटकम बजट 25 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत किया गया। इसे किस वित्त मंत्री ने पेश किया?
- पी. चिदम्बरम
- उस बजट को क्या कहा जाता है, जिसके तहत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद या शून्य मान लिया जाता है और बजट का आवंटन उस वर्ष की जरूरत के आधार पर किया जाता है?
- शून्य आधारित बजट (Zero Based Budget)
- शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन पिट पायर ने 1970 में किया। इस अवधारणा को सबसे पहले किस देश में अपनाया गया?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट को वर्ष 1983 में किस विभाग के बजट में अपनाया गया?
- विज्ञान व प्रौद्योगिकी
- भारत में जेडबीबी की अवधारणा का इस्तेमाल सातवीं पंचवर्षीय योजना (1988-93) में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस अवधारणा को किस नाम से इस्तेमाल किया?
- विकास आधारित बजट (Development Based Budget)
- जब बजट में लिंग विशेष (विशेषकर महिलाओं) के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया गया होता है, तो उसे किस बजट की संज्ञा देते हैं?
- जेंडर बजट
- उस कर को क्या कहा जा रहा है, जो किसी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ) द्वारा किसी अनुसूचित बैंक के गैर-बचत खाते से एक ही दिन में एक निर्धारित सीमा से अधिक के नकद लेन-देन पर लगाया जाता है?
- बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स
- वित्तीय वर्ष 2017-18 से रेल बजट का आम बजट में विलय हो गया। वित्त वर्ष 2017-18 में बजट प्रस्तुत करने की तिथि में भी बदलाव का निर्णय लिया गया, ताकि पहली तिमाही सहित पूरे कार्य सत्र का उपयोग सुनिश्चित हो सके। वित्त वर्ष 2018-19 से इसकी तिथि क्या हो गई है?
- 1 फरवरी

अतिरिक्त कर

शुद्ध आयकर में से दी गई निर्धारित कर छूटों को निकालने के पश्चात् भी यदि आयकर राशि निर्धारित उच्च आय वर्ग में आती है, तो इस पर निर्धारित आयकर प्रावधानों के अनुसार लगने वाले आयकर से अधिक आयकर की वसूली की जाती है, जो अतिरिक्त कर (Surcharge) कहलाती है। निर्धारित आयकर से अधिक आय की विभिन्न सीमाओं के लिए भिन्न-भिन्न अतिरिक्त आयकर वसूली दर निर्धारित की जाती है।

कार्बन कर

कार्बन कर ईंधन में कार्बन तत्वों (मुख्यतः कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस) पर लगाया जाने वाला कर है, जिनके जलने पर कार्बन का उत्सर्जन होता है। यह कर प्रति टन कोयला, प्रति बैरल तेल या प्रति मिलियन क्यूबिक फीट गैस की दर से लागू होगा। यह राशि कार्बन तत्वों पर लागू करों के समकक्ष समायोजित होगी। ऐसे कर का योजितकीकरण जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में है।

अग्रिम कर

अग्रिम कर (Advance Tax) अर्जित आय के आधार पर देय (Pay as You Earn) सिद्धांत पर आधारित है। अग्रिम कर प्रत्येक वर्ष मार्च, सितंबर एवं दिसंबर में देय होता है, ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के संबंध में अपनी राजस्व प्राप्ति को से अवगत हो सके।

राजकोषीय कर्षण

राजकोषीय कर्षण का आशय उस बड़े हुए कर के भार से है, जो बिना कर की दरों में परिवर्तन मुद्रास्फीति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इस स्थिति में बढ़ी हुई मजदूरी तथा वेतन आदि के कारण व्यक्ति ऊंचे कर स्लैब में पहुँच जाता है।

<div>  <div> आम बजट 2020-21 </div> </div>		<div>  <div> केंद्र सरकार का व्यय </div> </div>	
		2020-21 के लिए बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	
पेंशन	2,10,682	व्याज	7,08,203
रक्षा	3,23,053	आईटी और दूरसंचार	59,349
प्रमुख सब्सिडी	2,27,794	योजना एवं सांख्यिकी	6,094
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,54,775	ग्रामीण विकास	1,44,817
वाणिज्य और उद्योग	27,227	वैज्ञानिक विभाग	30,023
पूर्वोत्तर का विकास	3,049	सामाजिक कल्याण	53,876
शिक्षा	99,312	कर प्रशासन	1,52,962
ऊर्जा	42,725	राज्यों को अंतरण	2,00,447
विदेश मामले	17,347	परिवहन	1,69,637
वित्त	41,829	संघ राज्य क्षेत्र	52,864
स्वास्थ्य	67,484	शहरी विकास	50,040
गृह	1,14,387	अन्य	84,256
		कुल जोड़	30,42,230

- सरकार द्वारा किस समिति की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी तक लाने पर विचार किया जा रहा है? - **शंकर आचार्य समिति**
- योजनागत व्यय को सामान्यतः स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के रूप में मानते हैं, वहीं गैर-योजनागत व्यय को ऐसे व्यय के रूप में रेखांकित करते हैं, जो अस्थायी स्वरूप का हो। इन दोनों तरह के व्ययों को किस वित्त वर्ष से समाप्त कर दिया गया है? - **वर्ष 2017-18 से**
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभाग द्वारा किस नाम से एक अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क प्रारंभ किया गया है, जिस पर वस्तु एवं सेवा कर को भी लागू करने में तकनीकी सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है तथा जो वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को बैंक एंड आईटी अवसंरचना मुहैया करावेगा? - **सक्षम परियोजना**
- आयकर विभाग एवं एल एंड टी इन्फोटेक की किस संयुक्त परियोजना का उद्देश्य कर अपवर्धन करने वालों की पहचान करना तथा टैक्स बेस को विस्तृत करना है? - **प्रोजेक्ट इनसाइट**
- केंद्रीय सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात मार्च 2020 तक 46.7 प्रतिशत तथा मार्च 2021 तक 44.6 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अनुपात के मार्च 2019 तक कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? - **मात्र 48.8 प्रतिशत**
- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 में 3.4 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 में इसके कितने प्रतिशत (बजट अनुमान) रहने का अनुमान लगाया गया है? - **मात्र 3.3 प्रतिशत**
- वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के मुताबिक कुल सब्सिडी 2,62,108.76 करोड़ रुपये रही। इसमें सर्वाधिक हिस्सा किस सब्सिडी का है? - **खाद्य सब्सिडी**

मेरिट वस्तुएं

ऐसी निजी वस्तुएं, जो किसी वर्ग विशेष के लिए बहुत आवश्यक हों 'मेरिट वस्तुएं' कहलाती हैं, उदाहरण के लिए अल्पआय वर्ग के लिए आवास, शिक्षा आदि। प्रत्येक प्रकार की सब्सिडी मेरिट वस्तु का उदाहरण है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सौ. रंगराजन द्वारा जुड़वां मेरिट वस्तुएं कहा गया है।

सकल कर राजस्व की संरचना

कर	2018-19 (BE)	2018-19 (PA)
जीएसटी	33%	28%
कॉर्पोरेट कर	27%	32%
आयकर	23%	23%
कस्टम ड्यूटी	5%	6%
कं. उत्पाद शुल्क	12%	11%

BE: बजट अनुमान, PA: अंतिम वास्तविक आंकड़े

उपकर एवं अधिभार

सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए करों के ऊपर लगाये गए कर को उपकर (Cess) कहा जाता है, जैसे- शिक्षा सेस, डॉजल वाहनों पर पर्यावरण उपकर आदि। दूसरी तरफ, अधिभार (Surcharge) सरकार द्वारा पहले से लगाये गए करों को ही आधार बनाकर कर वसूला जाता है। उपकर संचित निधि का भाग नहीं हो सकता है, परंतु अधिभार हमेशा संचित निधि का भाग होता है।

समतुल्यीकरण लेवी

समतुल्यीकरण लेवी (Equalisation Levy) एक प्रकार का कर है, जो व्यापार से व्यापार (B to B) अंतरण पर लगाया जाता है। यह लेवी 6% की दर से 'विशेष सेवा' के लिए दिए जाने वाले धन पर लागू होती है। इसको किसी अनिवासी विदेशी ई-कॉमर्स कम्पनी द्वारा अर्जित आय के करधान के रूप में भी जाना जाता है। इसे 'गूगल कर' भी कहते हैं।

राजकोषीय नीति एवं सार्वजनिक वित्त

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST: Goods & Service Tax) कब से लागू किया गया? - 1 जुलाई, 2017 से
(नोट: 30 जून, 2017 को रात में संसद के संयुक्त अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने घंटी बजाकर जीएसटी को लागू करने की घोषणा की।)
- जीएसटी विधेयक को लोकसभा में मई 2015 में पारित किया गया। इसको राज्यसभा में कब पारित किया गया? - 3 अगस्त 2016 को
- भारत में जीएसटी लागू करने का मुद्दा किस समिति ने दिया था? - विजय केलकर समिति
- विश्व में सबसे पहले जीएसटी वर्ष 1954 में किस देश में लागू किया गया था? - फ्रांस
- चीन में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया? - वर्ष 1994 में
- भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? - कनाडा
- विश्वभर में कितने देशों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अपनाया है? - लगभग 160 देशों ने
- जीएसटी के वर्तमान में पांच स्तरीय कौन-कौन से हैं? - 0%, 5%, 12%, 18% और 28%
(नोट: जीएसटी के तहत वस्तुतः कर की चार श्रेणियाँ हैं।)
- किस देश में जीएसटी के सबसे ज्यादा स्तरीय या श्रेणियाँ हैं? - भारत
- भारत में सबसे उच्चतम स्तरीय 28 प्रतिशत का है। इस मामले में दूसरे स्थान पर कौन-सा देश है? - अर्जेंटीना (27%)
- भारत में जीएसटी के कितने प्रकार रखे गये हैं? - तीन प्रकार
(नोट: जीएसटी के तीन प्रकार हैं- सेंट्रल जीएसटी (Central Goods and Service Tax), स्टेट जीएसटी (State Goods and Service Tax) और इंटीग्रेटेड जीएसटी (Integrated Goods and Service Tax)।)
- भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? - 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
(नोट: यह 122वें संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया, लेकिन जब यह पारित हुआ तब यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना गया।)
- जीएसटी संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? - अनुच्छेद 279
- वस्तु और सेवा कर किस प्रकार के उपयोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है? - घरेलू उपयोग के लिए
- जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाले खुदरा कर (Retail Tax) की भाँति है। इस कर को किससे वसूला जाता है? - उपभोक्ता से
- जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है? - निर्मला सिधार्थन, वित्त मंत्री, भारत सरकार
- जीएसटी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? - 33
- जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? - नयी दिल्ली
- जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा है? - असम
- जीएसटी विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? - असीम दास गुप्ता
- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की घोषणा के मुताबिक जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? - 1 जुलाई को
- जीएसटी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? - एक देश, एक कर
- वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है? - देशभर में कर एकरूपता लाने और कर ढाँचे को एकीकृत करने के लिए
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) किस प्रकार का कर है? - अप्रत्यक्ष कर
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एकीकृत कर प्रणाली है। इसमें कितने अप्रत्यक्ष करों को मिलाया गया है? - कुल 17
(नोट: अब हर राज्य में अलग-अलग कर नहीं लगे। बल्कि देशभर के लिए एक जीएसटी होगा।)
- क्या कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, ड्यूई ईंधन, प्राकृतिक गैस और डीजल को जीएसटी के अन्दर शामिल किया गया है? - नहीं
- क्या जीएसटी में सेवा कर को शामिल किया गया है? - हाँ
- क्या जीएसटी में सबको रिटर्न भरना होगा? - नहीं
- कितनी राशि का कारोबार करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को जीएसटी का रिटर्न भरना पड़ेगा? - 20 लाख रुपये से अधिक
- दूध और घी में से किसको जीएसटी से बाहर रखा गया है? - दूध को
- कानून पर जीएसटी पहले 12 प्रतिशत लगाने का प्रस्ताव था जिसे बाद में घटाकर कितना कर दिया गया? - मात्र 5 प्रतिशत
- क्या बिक्री कर और वैट अलग से चुकाना होगा? - नहीं
(नोट: बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और वैट को जीएसटी में मिल दिया गया है। इसलिए इन्हें अलग से चुकाने की जरूरत नहीं होगी।)
- क्या जीएसटी से रान्धो में प्रवेश कर या चुंगी कर (Octroi) समाप्त हो जाएगा? - हाँ
(नोट: अब प्रवेश कर (चुंगी) को समाप्त कर जीएसटी में ही मिला दिया गया है।)
- कर से छूट वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जो बिल बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? - बिल ऑफ सप्लाय
- जीएसटीएन (Goods and Services Tax Network) किस अधिनियम के तहत आता है? - कंपनी अधिनियम 2013
- जीएसटीएन में केंद्र और राज्य सरकारों का हिस्सा बराबर-बराबर है। यह कितना प्रतिशत है? - 49 प्रतिशत
- जीएसटी नेटवर्क से सम्बद्ध आईटी कंपनियाँ कौन-सी हैं? - इन्फोसिस और विप्रो
- जीएसटीआईएन का पूरा नाम क्या है? - गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईडेंटिफिकेशन नंबर
(नोट: जीएसटीआईएन या जीएसटी आईडेंटिफिकेशन नंबर एक अद्वितीय 15 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापार की पहचान करने के लिए किया जाता है।)
- पहले कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न के लिए 12 फॉर्म भरने पड़ते थे। 1 जनवरी, 2020 से वर्षभर में कितने रिटर्न भरने पड़ेंगे? - मात्र 4
- सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर, 2020 को दिये गये अपने एक फैसले में लॉटरी, जुआ और शर्त के खेल पर जीएसटी की वसूली को सही ठहराया। इन पर किस दर से कर लगाया जाता है? - 28 प्रतिशत